



कोरबा 13-01-2026

एसईसीएल

कमेटी ने वेतन विसंगति दूर करने पे-अपग्रेडेशन की अनुरासा की है, लागू करने पर वेतन में 20 हजार रुपए की वृद्धि होगी

कोयला अफसरों के वेतनमान में बदलाव पर कोल इंडिया लेगा फैसला

कोयला अफसरों के वेतनमान में बदलाव पर कोल इंडिया ने निर्णय अदान करवा है। कोयला अफसरों के 11 में वेतन समीक्षा से अपने अधिकारियों के वेतन विसंगति को दूर करने गठित कमेटी ने मशरत कर्पनी के अनुसार कोल इंडिया के अफसरों को पे-अपग्रेडेशन देने की अनुशंसा की है। इसी मसल जुलाई 2026 से कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए 12 वर्ष वेतनमान लागू होगा। ऐसे में

वेतनीयताआई कमेटी का गठन भी किया गया है।कोल इंडिया में 11 वर्ष वेतन समीक्षा के बाद कई कर्मचारियों का वेतन अधिकारियों के समकक्ष हो गया। वेतन विसंगति दूर करने की यात्रा पर कोल इंडिया ने कमेटी का गठन किया। कमेटी ने प्रस्तावित वेतन वृद्धि के साथ रिपोर्ट तैयार की है। इस प्रस्तावित वेतन वृद्धि की अनुशंसा को कोल अफसरों ने केंद्रगत मंत्रालय से स्वीकृति मिलने की जानकारी दी है। इसके बाद से अब कोयला अफसरों के वेतनमान में बदलाव की अनुशंसा पर कोल इंडिया के निर्णय पर निर्भर दिखे हुए है। कोल इंडिया में प्रस्तावित वेतन

बढ़ोतरी को लागू करने पर अधिकारियों के वेतन में 20 हजार रुपए से अधिक की वृद्धि होगी। इसका लाभ ई-1 से ई-7 तक के अधिकारियों को लाभ मिलेगा। कोल इंडिया में अफसरों को वेतन वृद्धि का लाभ किस तरीके से मिलेगा, इस पर भी यथावत होने लगी है। हालांकि कोल इंडिया के निर्णय अदान के बाद ही यह पूरा तक स्पष्ट होगा। पिछले साल कोयला अफसरों के वेतनमान में 19 फीसदी वृद्धि के साथ विसंगति का लाभ दिया गया था। इस बार कम रकम की इसी वृद्धि की विसंगति दूर करने के लिए कमेटी ने अनुशंसा की है।

कमेटी की अनुरासा को लागू करना इसलिए भी जरूरी है

कोयला अफसरों के वेतन बढ़ोतरी संबंधी गठित कमेटी की अनुशंसा को इसलिए भी लागू करना जरूरी है क्योंकि कोयला अफसरों के वेतन समीक्षा वर्ष 2026 तक है। सुनाई गइने से विविध गारंटी बेनिफिट (एम्प्लॉयी) का लाभ देकर नए वेतनमान लागू किया जाय है। अभी कोल इंडिया में कर्मचारियों के लिए लागू वेतन समीक्षा के कारण अफसर-कर्मियों के बीच वेतन विसंगति बरकरार आई है। ऐसे में नए वेतनमान से यह वेतन विसंगति दूर होगी। इसलिए इस पर तुरंत निर्णय कोल इंडिया को लेना होगा।

ग्रेजुटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की

कोल इंडिया की ओर से ईटएच के समय कर्मचारी अधिकारियों व नए वृद्धि-वृद्ध सुधारकार्यों को मिलने वाली ग्रेजुटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। इससे अधिकतम गरी होने के बाद एक्टुअल गैरगन ने कर्मचारियों को ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग उठाई है। अधिकारियों की ग्रेजुटी सीमा बढ़ाने का निर्णय औद्योगिक मंत्रालय भी 50 प्रतिशत के दर बढ़ाने पर किया है। इसका लाभ एम्प्लॉयमेंट सर्विस कोल इंडिया के द्वारा कर्मचारियों के अधिकारियों को मिलेगा।

एसईसीएल आगे की रणनीति पर कोयला विचार: राठौड़

अंतर इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एम्प्लॉयमेंट के संयोजक पीके राठौड़ ने कहा कि अप्रैल 2026 तक ही कोल वेतन विसंगति दूर होना होगा, कमेटी का नकार अदान के बाद यह स्पष्ट रूप से यह वेतन विसंगति दूर करनी होगी, कमेटी का निर्णय ही, अधिकारियों का वेतन विसंगति दूर करनी होगी।



कोरबा 19-01-2026

सोईएमपीएफओ में डिजिटल सुधार • पीएफ व पेंशन दावों का ऑनलाइन निपटारा करने सी-केएस पोर्टल किया अपग्रेड कर्मियों को रिटायरमेंट के दिन ही खाते में मिल रहा पीएफ

कोयला कर्मियों को पीएफ की रशि रिटायरमेंट के दिन ही बैंक खाते में मिल रही है। ऐसी व्यवस्था कोयला खान अफिस निर्णय संकलन (सीएमएफओ) में जल्दी डिजिटल सुधार के बाद हुई है। साथ ही पीएफ व पेंशन दावों व रिक्वायर्स का ऑनलाइन निपटारा करने सी-केएस पोर्टल अपग्रेड किया है। सी-केएस पोर्टल का संस्करण 2.0 में सीएमएफओ के सदस्यों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन भी है, जिससे सदस्य रोजगार प्रोत्साहन के साथ ही पानी की टैक कर सकते हैं। सदस्यों को अपग्रेड पीएफ बैंक खाते को

अनवरुत मिल रही है। नए वित्तीय संबन्धन लागू होने से अफिस निर्णय की रशि सदस्यों के खातों में उभरी दिन भेज रहे हैं। इससे पहले औसतन 7 दिन का समय लग जाता था। कोयला खान क्षेत्रों में पेंशन प्रकरण के उचित समन्वय संचालन करने, सामरिक सुलभ तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने और धार-धार जाकर पेंशन और पेंशन विवरण जैसी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जून 2025 में मिशन प्रकल्प शुरू किया गया। इसका लक्ष्य कोयला कर्मचारियों तक पहुंचाना, उनको पेंशन एवं पेंशन दावों का निपटारा करना था। सी-केएस पोर्टल से अब पीएफ व पेंशन मामलों की अधिकतम रिपोर्ट

पीएफ से जुड़ी शिकायतें नहीं रहेंगी, पेंशन में हो बढ़ोतरी

अंतर इंडिया कोल एसोसिएशन के संयोजक पीके राठौड़ ने कहा कि नई व्यवस्था से सीएमएफओ सदस्यों के पीएफ व पेंशन से जुड़ी शिकायतें दूर होंगी। मंत्रालय से पेंशन बढ़ोतरी पर केन्द्र सरकार उदात्त है। इसे लेकर एसोसिएशन को बैठक में भी वित्त मंत्रालय की राई। साथ ही कोयला कर्मियों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग पर चतुष्टय आंदोलन किया जाएगा। कई कोल पेंशनरी को 1 हजार रुपए से भी कम पेंशन मिल रहा है। जबकि कोल इंडिया में न्यूनतम 1 हजार रुपए पेंशन पर सशक्ति बने भी।

कोयला हुआ है। वही लक्ष्य अदान के अंतर्गत की निष्पत्ति मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से रिक्त रखन देखा संकेत। इससे पारदर्शिता बढ़ी है। पेंशनरी के अदान के अभाव तक देरी से भी निवार मिली है। पहले अभाव का नाम में

इसी साल तक जीरो पेंडिंग शिकायतें करने का लक्ष्य

सीएमएफओ में डिजिटल सुधार के बाद पीएफ व पेंशन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में तेजी आई है। 2026 तक जीरो पेंडिंग शिकायतें करने का लक्ष्य है। क्योंकि अब शिकायतों के समाधान में लगने वाला समय घट गया है। 2024 में शिकायतों के निपटारे की औसत 21 दिन, 2025 में 15 दिन और अब 2026 के लिए अधिकतम 7 कार्य दिवस में समाधान का लक्ष्य रखा गया है। शिकायतों की निष्पत्ति रिक्त रखन देना मंत्रालय के माध्यम से भी कर रही है। इस तरह सीएमएफओ शिकायतों के मामलों में जीरो पेंडिंग की ओर बढ़ रही है।

and All India Coal Pensioners Association will hold a dharna in front of the Kothagudem headquarters under the auspices of All India Coal Pensioners Association Kanwar PK Singh Rathod, Singareni Retired Employees Welfare Association President Dandam Raju Ramachandra Rao and General Secretary Alavandar Venumadhav said in a statement that they will demand that the problems of Singareni pension workers be resolved. They demanded that the coal pension increase be revised, the difficulties faced by pensioners for CPRMS medical cards and the long-pending issue be resolved. He said that due to the delay in the legislative amendment to the Coal Mines Provident Fund Act, 1948, pensioners are facing serious difficulties due to deficiencies in medical treatment, reimbursement and medical card benefits under the CPR MS, and he strongly condemned the officials for treating them as if they were not responsible. He said that a protest dharna will be held in March to bring this to the attention of the authorities in a democratic manner. He asked the Singareni management to respond immediately and resolve the long-pending problems of pensioners. Leaders M. Vijay Babu, T. Umakar, Narsing Rao, Beeriah, B. Kanakaiah, Rajaiah and others participated in this program.

30/01/2026 | Adilabad District | Page : 4
Source : <https://epaper.teluguprabha.net/>

Translated with  Google Lens

Pensions for retired workers should be increased.

Srirampur, January 29 (Andhra Jyoti): Pension for retired workers Singareni Retired Employees Welfare Association President Dandamraju Ramachandra Rao and Deputy General Secretary Alavandar Venumadhav demanded an increase in pension. They spoke locally on Thursday. They said that the All India Association of Coal Executives and All India Coal Pensioners Association met on the 18th of this month to organize a movement to resolve the issues related to pension increase, issuance of revised pension payment orders, and difficulties faced by pensioners in using CPRMS (medical card). On this occasion, they said that they have decided to hold dharnas in Talcher, Kothagudem and New Delhi in the month of March. He explained that All India Coal Pensioners Association convener P.K. Singh Rathod has written a letter to the Singareni management requesting them to resolve the pending issues regarding retired workers. _ He said that they are hoping for a positive response from the management.

Translated with  Google Lens

Resolve pending issues

New Telangana-Jaipur

The All India Coal Pensioners Association officials are demanding that the long-pending issues faced due to coal pension hike, issuance of revised pension payment orders, and CPRM cards be resolved. To this end, the association officials stated that a virtual meeting was recently held under the auspices of the association, several decisions were taken to resolve the respective issues, a letter was written and sent to the Singareni Chairman and Managing Director. The association officials stated that it was unanimously decided to restart the democratic agitation program for detailed pension hike and related demands to bring the issues to the attention of the Singareni management. The association officials stated that the letter stated that a one-day dharna will be held in Kothagudem in March 2026 and the date will be announced in advance. In a letter written to Singareni Retired Employees Welfare Association President Dandamraju Ramachandra Rao and General Secretary Alavandar Venumadhav, the association convener PK Singh Rathod stated that they have taken up a democratic and peaceful protest to draw the attention of the concerned authorities to the serious difficulties faced by coal pensioners due to the immense delay in amending the Minority Pension and Coal Mines Provident Fund Act, 1948, and the shortcomings in medical, reimbursement and medical card benefits under the amended CPRMS in many cases. They also stated that the association convener PK Singh Rathod should understand the seriousness of the problem and extend their support to them.

30/01/2026 | MANCHERIAL | Page : 4
Source : <https://epaper.navatelangana.com/>

Translated with  Google Lens

**ABN Andhra
Jyothi**

We will again mobilize for pension reform.

Srirampur, February 7 (Andhra Jyoti): Retired after working in the coal sector The All India Association of Coal Executives and the All India Coal Pensioners Association have decided to jointly agitate for an increase in the pension of employees. The leaders of the respective associations took key decisions in a meeting held through Google Meet. Speaking, the association's vice president BK Srivastava said that despite holding a dharna in Kolkata on September 15 last year, there was no response from the government. Coal Pensioners Association convener PK Singh Rathod said that the main demand should be to fight for a pension increase. He also said that the CMPF has completely failed to protect the funds deposited by the employees. He demanded that the corpus fund be paid to the pensioners if the pension cannot be increased. He said that they had also given suggestions in the draft CMPF bill, but the bill has not been introduced in Parliament yet. He said that they have decided to hold a huge dharna in New Delhi on March 30 on pension increase and other issues. Later, they said, they will hold protests in other areas as well. Representatives from Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh, and other states participated in the Google Meet in large numbers and expressed their support.

08/02/2026 | Mancheriala District | Page : 2

Source : <https://epaper.andhrajyothy.com>

Translated with  Google Lens

Pravachanam Talukar Daily

Public purpose

Talukar Daily News Agency
www.talukardaily.com

08 Feb 2026 | Editor: Goli Sammi Reddy | Page 7
Source: epaper.prajalakshyam.com

All India Coal Pensioners' Dharna Date Finalized

- Massive protest in New Delhi on March 30



(Public representative)
Hyderabad, February 7. The All India Coal Pensioners Association (AICPA) has decided to hold a massive protest in New Delhi on March 30 to resolve the issues of coal pensioners. A virtual meeting was held under the auspices of AICPA on February 5, 2026 to decide on the dates, times and locations of the dharna events. About 70 members from across the country attended the meeting. The meeting was presided over by Dr. B.K. Srivastava, Vice President of All India Coal Executives Association. He said that we have been waiting patiently since the last dharna held in Kolkata on September 15, 2025, but now the time has come to start the agitation again. AICPA/AICE Convener P.K. Singh Rathore explained the steps taken so far on pension revision, issuance of revised PPOs and empanelment of hospitals. However, he clarified that the main issue is the pension revision. After the dharnas held in New Delhi, Varanasi and Dhanbad and the landmark dharna held in Kolkata on September 15, 2025, the Coal Ministry released a draft of the Coal Mines Provident Fund Bill, but it has not been introduced in Parliament so far. Pension is our right and it is our responsibility to use the funds judiciously so that retirees get adequate pension.

He alleged that the CMPFT is a corporation, but that the organization has failed to discharge its responsibilities properly. He demanded that if the pension cannot be increased, at least the pension corpus should be paid back to the pensioners. He said that in the last meeting held on January 18, 2026, it was decided to organize dharnas in Talcher, Kothagudem and New Delhi in the month of March. On this occasion, the views of the members were invited. Dr. B.K. Srivastava, speaking, suggested the possibility of organizing dharnas in three phases in March. However, All India Association of Coal Officers Vice President S.N. Singh criticized that so far there have been empty promises and no clear actions. He called for intensifying the movement even if it is necessary to face arrests and for members to attend in large numbers to make the dharnas successful.

Pawan Tandon, on behalf of the All India Coal Pensioners Association, suggested that the agitation should not be delayed any further and that the dates be fixed in advance keeping in mind the festivals. Shri N.C. Sahu from Talcher said that the members there were interested in participating in the dharna rather than the rail roko. He revealed that the issue had been brought to the notice of the Chief Minister of Odisha. Dinkar Sahu and Shyamal Sahu from Betal assured that about 1000 members would participate in the dharna. D. Ramachandra Rao and A. Venumadhav from Hyderabad said that a large number of representatives from Telangana and Andhra Pradesh states would participate. After extensive discussions, a final decision was taken to organize a huge dharna in New Delhi on March 30, 2026. It was announced that agitations would be held in other places in the next phase if necessary. The All India Coal Pensioners Association has appealed to current and retired employees and their families to participate in the movement, saying that the pension amendment will benefit all coal employees and pensioners.

Translated with  Google Lens

Prajalakshyam Telugu Daily

Prajalakshyam Telugu daily newspaper

Editor: Goli Sammi Reddy

08 Feb 2026 | Editor: Goli Sammi Reddy | Page 7

Source: epaper.prajalakshyam.com

Retired Employees Welfare Association letter to Singareni CMD

(Public representative)

Hyderabad, February 7: The Singareni Retired Employees Welfare Association has submitted a letter to the Singareni CMD seeking to resolve the problems of retired employees of the Singareni Collieries Company. The retired employees of the Singareni Collieries Company are currently living in various parts of the state. The Singareni Retired Employees Welfare Association stated that these retired employees, who are suffering from chronic diseases like BP and diabetes along with old age, have to travel from far away places to get medicines at



Singareni hospitals every month. In this context, the Singareni Retired Employees Welfare Association said that the association leaders have written a letter to the Singareni Chairman and Managing Director, requesting that the medicines be distributed once in two months instead of once a month, and that a super specialty hospital be set up in Hyderabad as promised earlier by the management and that appropriate medical services be provided to the retired employees without any restrictions. Among those who presented this letter were association president Dandamraju Ramchandra Rao, general secretary Ala Vandar Venu Madhav, as well as M. Vijaya Babu, T. Umakar, S. Narsingh Rao, Beeriah, G.V. Raji Reddy, and G. Kanakaiah.

Translated with  Google Lens

Movement for pension reform resumes

Massive protest in New Delhi on March 30

Joint decision of All India Association of Coal Executives--All India Coal Pensioners Association

Singareni Representative February 07, Journalist Telugu Daily News:

The All India Association of Coal Executives and the All India Coal Pensioners Association have jointly decided to intensify the movement again on the demand for pension revision of coal sector pensioners. Key decisions were taken in a meeting held on February 5, 2026 through Google Meet. About 70 members attended the meeting and Dr. BK Srivastava, Vice President of the Association, presided over it. He made it clear that there was no stopping after the government's lack of response after the dharna held in Kolkata on September 15, 2025, and that the time has come to restart the movement. Coal Pensioners Association Convener PK Singh Rathore said that the main demand was the pension revision and alleged that the Coal Mines Provident Fund had failed as a custodian of funds. They demanded that the pension fund deposit be returned to the pensioners in a situation where pension could not be increased. Although they gave their suggestions on the draft Coal Mines Provident Fund Bill,

The meeting was concluded with gratitude for the far. Dissatisfaction was expressed. After the discussion on the outline of the movement, although a proposal was made to hold dharnas in three places initially, after extensive discussions, the final decision was taken to hold a big dharna in New Delhi on March 30, 2026. It was announced that dharnas would be held in other places later if necessary. Representatives from Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, Madhya Pradesh and other states participated in the meeting in large numbers and expressed full support. The pension revision is beneficial to all employees - current and retired, and the leadership called on them to participate in the movement along with their families. In this meeting, Singareni Retired Employees Welfare Association President Dandam Raju Ramchandra Rao and General Secretary Alavandar Venu Madhav participated and said that they are working hard to consult ministers and MPs for the pension revision, and a large number of representatives from Telangana will participate in the dharna. At the end of the meeting, R.A. Manjunath Prasad bill not being introduced in Parliament so

Translated with  Google Lens

A separate coal pensioners portal should be established for coal pensioners.



New Telangana-Jaipur

Leaders of the Retired Singareni Employees' Welfare Association have requested the establishment of a special portal for coal pensioners for the convenience of the six lakh coal pensioners across the country. Recently, the CMPF office officials in Godavarikhani were asked to take appropriate steps to resolve the problems of coal pensioners. Meanwhile, coal pensioners across the country are expressing their concerns that they are facing financial difficulties due to the very low pension. For the convenience of coal pensioners, they are demanding that the EPF portal be provided to the defense pensioners with digital access to pension payment orders, pension slips, pension statements, real-time pension credit tracking, etc. to contact banks. Similarly, he said that the integrated grievance redressal mechanism and the Jeevan Pramaan app will be implemented without mandatory login, and the digital life certificate will be submitted directly on the portal through video verification. He said that in today's digital era, since the Aadhaar number of coal pensioners is already linked to the pension bank account, there is a need to introduce a separate coal pensioners portal for coal pensioners. As a result, pensioners are able to complain to the concerned authorities through the portal without having to go around the CMPF office and banks when they do not receive their pension. Coal India Pensioners Association Convener PK Rathore reminded that a letter has been written to the Central Coal Mines Provident Organization Commissioner Dhanbad office in this regard. Singareni Retired Employees Association expresses its gratitude to the Central Coal Mines Provident Organization for writing a letter for the convenience of coal pensioners, said General Secretary Alavandar Venumadhav and Mancherial District Honorary President Rallabandi Rajaraja.

न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन लागू करना

- 30 मार्च को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ।
- एआईसीपीए/एआईएसीई संयोजक पी.के. सिंह राठौर का आह्वान



सोल्डर ₹1000 करना वंच योजना को मजबूत कर दें।
मधेसियाल, 6 मार्च (प्रजा ज्योति): कोयला एआईसीपीए/एआईएसीई के संयोजक पी.के. सिंह राठौर ने बुधवार को कहा कि ग्लोबल पैशनर्स गिरो को प्रति माह 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही थी, उनके लिए न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये लागू बन दी गई है।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के कारण बकाया राशि भी पैशनर्स गिरो को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि एआईसीपीए/एआईएसीई सदस्यों के निरंतर संघर्ष और कड़ी मेहनत इस सफलता का मुख्य कारण है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशन संशोधन की मांग पूरी तरह से पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया कि 30 मार्च को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विशाल धरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने देश भर के सदस्यों और कोयला पैशनर्स गिरो से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर धरने को सफल बनाने का आह्वान किया। राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी 30 मार्च को होने वाले धरने पर ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें 5 मार्च को दिल्ली से फोन आया था और प्रस्तावित धरने के बारे में जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है कि किस राज्य से कितने लोग भाग लेंगे, वे दिल्ली में कहां रुकेंगे और कार्यक्रम की योजना क्या होगी। राठौर ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि पेंशन संशोधन के लिए धरने में 90 वर्ष की आयु के सदस्य भी भाग ले सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब संघर्ष का समय आ गया है और पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एआईसीपीए/एआईएसीई के सहयोग से ही यह संभव है।

Translated with Google Lens

ILO should intervene on CMPF pension issue

Email of AICPA and AIACE representatives

(Public representative)

Hyderabad, March 11: Representatives of AICPA and AIACE have appealed to the International Labour Organization (ILO) to intervene in the issue of meager pensions being received by coal miners in India under the Coal Mines Pension Scheme. To this end, the representatives of the association said on Thursday that they have sent a letter of representation to the Director General of the International Labour Organization through e-mail on behalf of the All India Coal Pensioners Association (AICPA) and the All India Association of Coal Executives (AIACE). This appeal was sent by AICPA convener P.K. Singh Rathore through e-mail. According to the letter, coal miners have worked in extremely dangerous conditions during their service and have made immense contributions to the industrial development and energy security of the country. However, after retirement, many workers have to live on a pension that is not even enough for a minimum livelihood. Coal Mines Pension is currently administered by the Coal Mines Provident Fund Organization (CMPFO).

It was stated that many pensioners under the scheme are getting only a monthly pension that is too low for a dignified life. They said that despite their associations having appealed to the Coal Ministry and the concerned authorities on this issue several times, no appropriate action has been taken. In this context, they have requested that the minimum pension be increased significantly that the pension be linked to inflation with the Dearness Relief (DR) mechanism, and that the pension be revised from time to time keeping in mind the cost of living. They also suggested that a transparent digital portal be set up for CMPF pensioners and pension administration should be improved. In the absence of a proper response from the concerned government agencies, the coal pensioners' associations have decided to hold a peaceful dharna at Jantar Mantar, New Delhi on March 30, 2026 to focus on this long-standing issue. They appealed to the International Labour Organization, which is committed to protecting labor rights and social security standards, to look into this issue, bring it to the notice of the concerned authorities and show the way for a solution.

We have sought the intervention of the International Labor Organization on the plight of coal pensioners.



Peaceful dharna at Jantar Mantar on March 30 by - P.K. Singh Rathore



He expressed his concern that the pension currently being received by coal miners under the Coal Mines Pension Scheme run by the Mines Provident Fund Organisation is very low. Rathore reminded that coal miners have worked in extremely dangerous, underground conditions for decades for the industrial development and energy security of the country. However, the pension they receive after retirement is not even adequate for basic livelihood, and despite their associations submitting several representations to the Coal Mines Provident Fund Organisation, the Coal Ministry and other concerned authorities on this issue, there has been no proper response.

Keeping in view the rising cost of living, they are demanding a significant increase in the minimum pension in the coal pension scheme, and provision of drought relief by linking the pension to inflation. Similarly, the unions are also demanding a system of periodic revision of pension and the establishment of a transparent digital pensioner portal for coal mines pensioners. Rathore said that a peaceful dharna will be held at Jantar Mantar in New Delhi on the 30th of this month, demanding that the government take immediate action on this long-pending issue. He made it clear that providing a dignified pension to coal miners who have served the country is a matter of social justice as well as human dignity. We hope that the International Labour Organization will kindly look into this matter and extend its moral support to resolve the issue of coal pensioners in India, P.K. Singh Rathore said.

Mancherial, 12. March (Prajajyoti): Millions of people in India All India Coal Pensioners Association convener P.K. Singh Rathore said that retired coal miners are facing severe financial difficulties due to very low pension. He said that the Director General of the International Labour Organization (ILO) has appealed to him through an e-mail to intervene in this problem. The All India Coal Pensioners Association said that this request has been sent on behalf of the All India Association of Coal Executives. Coal

Coal miners' pension hike is urgent

- Singareni Retired Employees Welfare Association General

- Secretary Alavandar Venu Madhav has called for support for a peaceful protest at Jantar Mantar on March 30.

Mancherial, 12th March (Prajya Jyoti):

Coal industry plays a key role in the development of India's economy, but coal miners who have worked hard all their lives for the development of the country are facing serious problems due to low pension after retirement, said Alavandar Venu Madhav, leader of coal retired employees. He urged the government to immediately increase the coal mines pension. He said that many sectors like power generation, steel industries,

cement industries are dependent on coal. He said that the miners who extract this coal from the depths of the earth work in dangerous conditions and devote their energy to the development of the country.

However, it is sad that the pension they receive after retirement is very low. He said that working in coal mines is one of the most dangerous jobs in the world. He said that while working in mines, workers face many dangers like dust, toxic gases, and underground accidents. He said that sometimes incidents like mine collapses, explosions and fires also happen. He said that workers who worked in these conditions are more likely to face health problems like lung diseases, respiratory problems and heart diseases after retirement. Pension for coal miners



He said that although it is provided by the Provident Fund Organization, according to the currently implemented pension scheme, many retired workers are getting only a pension of up to Rs 1,000 per month. He said that due to rising inflation, expenses like food, medicine, electricity, house rent etc. have increased drastically. He said that it has become very difficult to live with a low pension in such circumstances. Keeping these circumstances in mind, he demanded that the minimum pension for retired coal mine workers be increased to at least Rs 10,000 and that drought allowance (DA) should also be added to the pension. He said that this would increase the pension when prices increase. He said that the

YO.SHARE. The government will never forget the services rendered by coal miners. development of the country should not be forgotten. He said that it is the responsibility of the government to provide a dignified life to the workers who have worked in dangerous conditions all their lives and contributed to the development of the country's industries. In this context, All India Coal Pensioners Association Convener P.K. Alavandar Venu Madhav urged all retired coal miners to support the peaceful protest at Jantar Mantar, New Delhi, on March 30, as called by Singh Rathore. He also urged the government to improve medical facilities, social security and other welfare schemes for the welfare of retired coal miners.

<https://thewire.in/rights/many-have-passed-away-waiting-retired-coal-workers-demand-pension-revision-pending-for-three-decades>

‘Many Have Passed Away Waiting’: Retired Coal Workers Demand Pension Revision Pending for Three Decades



Sharmita Kar

The pensioners, all of whom are now in the age bracket of 60-90 years, say that their pensions have never been revised despite a mandate to review the amount every three years.



Workers at the North Dadhu coal block in Jharkhand. Photo: PTI

New Delhi: Retired coal workers across the country are planning a fresh protest as their pensions have not been revised since the time of their retirement, with several top-level executives getting less than Rs 10,000 per month.

The retired employees – mainly from Singareni Collieries Company Limited (SCCL), Coal India Limited (CIL) and their subsidiary companies – have alleged that the pension amount which, as per the Coal Mines Pension Scheme, 1998, is to be reviewed every three years has not been revised since inception. Additionally, the 1998, 2007 and 2017 wage revisions for employees were also not applied to these pensioners.

“There are more than five lakh coal pensioners whose pensions have not been revised. Many have even passed away waiting,” said Venu Madhav, a retired SCCL employee, who has been advocating for pension revision for years.

While the government raised the minimum monthly pension rate in 2024 to Rs 1,000 for those getting even lesser, many mid-to-senior-level retired employees continue to receive meagre monthly pensions that have not kept pace with inflation.

SCCL and CIL are both public sector undertakings under the administrative control of the Union coal ministry. However, these pensioners have been overlooked despite the pensions of other central government employees **having been enhanced** from time to time as per the Unified Pension Scheme.

Similarly, the pension amount for employees of other public sector enterprises and public sector undertakings – like Gas Authority of India Ltd, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation and public sector banks – have also increased over the years.

The Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO), the autonomous body which provides for the pension of coal sector employees, and falls under the Union coal ministry, has repeatedly told the pensioners that due to a shortage of funds, they have not revised the pensions.

Pensioners have, however, countered this in a petition in the Delhi high court, stating that the fund has grown over the years.

‘Government not doing anything for us’

Rayanna P.B. worked at SCCL, Telangana for 33 years before retiring as the chief transport officer with a basic pay of Rs 40,000 in 2006. Seventy nine now, he gets a pension of Rs 8,087 per month, the same as 20 years ago.

“We work so hard for so many years, take risks on the job, inhale coal dust regularly, yet the government is not doing anything to improve our lives,” he alleged.

Ramachandra Reddy B., another SCCL retiree who retired as a general manager of civil operations in 2002, said, “I was on one of the higher pay brackets. Yet, my pension, which was Rs 4,000 at the time, has not been revised to date.”

In 2002, Reddy drew a basic pay of Rs 23,600, which he said was equivalent to nearly Rs 1 lakh, with the wage revisions for employees since. “What good is Rs 4,000 today to run daily expenses?” the 82-year-old asked.

Like him, Prabir Kumar Mukherjee, a retired CIL executive, who gets a monthly pension of Rs 9,977, said, “The basic pay of employees has increased over the years. The 2007 and 2017 wage revisions

provided for handsome revisions for newer employees, making way for better pensions too. However, for us, in 27 years, there has been no pension revision.”

“The Coal Mines Provident Fund Organisation keeps saying that they do not have funds and so cannot increase the pension rate. The government is taking no action in this regard,” Mukherjee said.

Madhav said, “The central government keeps talking about ‘*atmanirbharta*’, they ask us to be ‘*atmanirbhar*’, but how will we be if we remain so poor? So many industries are dependent on coal and coal workers – power supply being at the top. It is a dangerous job that we do, there are health risks involved. Yet, we are not given enough pension or benefits to even pay medical bills.”

A Bill yet to be tabled in the parliament

The retirement age for coal mine employees is 60 years. Many of the protesting pensioners are in the age bracket of 70-90 years now, facing serious health problems and struggling to meet daily expenses.

The Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948, was last amended in 1996. The Coal Mines Pension Scheme, which replaced the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971, came into effect on March 31, 1998, to provide monthly pension benefits to retired coal miners, and was covered under the 1948 Act.

In October 2025, 77 years after the 1948 Act’s enactment, and following years of protests by coal pensioners, the Union government announced an overhaul by proposing a draft Bill, titled the [Coal Mines Employees’ Provident Fund and Miscellaneous Bill, 2025](#).

The Bill has not been tabled in the parliament yet. In a letter to the coal ministry, dated October 15, 2025, the All India Association of Coal Executives (AIACE) and All India Coal Pensioners Association (AICPA), demanded restructuring of the pension scheme to include the pensioners’ demands – a substantial increase in coal pensions, linking pensions to inflation and ensuring financial security and dignity for retired coal workers who dedicated their lives to building the nation’s coal industry.

The associations also sought a timeline for the preparation and implementation of a new pension scheme under this Bill to ensure the introduction of a Dynamic Pension Scheme with built-in Dearness Relief (DR) linkage without requiring parliamentary amendment, as per the letter. DR is additional payment to pensioners to ensure the pay keeps up with inflation.

'No dearness allowance'

The AIACE and AICPA has organised similar protests several times in the past too, including in 2019, 2022, 2023 and 2025.

Speaking to *The Wire*, P.K. Singh Rathor, convener of the AIACE-AICPA, said that in so many years, there was also no provision for dearness relief in the scheme. "As a result, even someone who retired at the top level may be getting something around Rs 3,000 because their pension was never revised," he said.

In a supplementary letter, the coal employees' body said, "In the 27 years since the pension scheme's inception, no comprehensive revision or actuarial rebalancing has ever been implemented. The pension amount paid to retired coal employees is grossly inadequate – in many cases less than Rs 1,000 per month – rendering the scheme socially meaningless and financially exploitative.

"The Court case and representations for enhancement of pension over two decades show a complete failure of fiduciary responsibility and erosion of pensioners' faith in the system," the letter added.

When *The Wire* reached out to the coal ministry, it reverted with the standard response that the CMPFO "does not have sufficient funds to sustain an increase in pension".

According to Chetna Shukla, deputy director general at the coal ministry, matters of pension revisions are dealt "on a case-to-case basis".

The Wire also reached out to the CMPFO commissioner regarding the status of the revisions. Assistant Commissioner, CMPFO, Madhuresh Kumar Singh pointed to a Rs 47 crore-deficit in funds. "The matter is under review. Decisions are taken by the board of trustees. We do not know anything about it," he said.

'They claim insufficient funds, but the companies are making a profit'

P.T. Rao, who retired in 2001 as a senior finance executive from the SCCL in Telangana, receives a mere Rs 5,000 as monthly pension. "We have approached the central government many times, written to the prime minister, coal minister, etc. They keep saying they don't have sufficient funds but the companies are making profits," he alleged.

In July 2025, the parliament's Public Accounts Committee (PAC), chaired by Congress general secretary and Lok Sabha member KC Venugopal, [tabled its report](#) in the House saying that the "failure of Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO) to take timely decision to redeem debentures of Diwan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) resulted in [an] avoidable loss of Rs 315.35 crore".

The PAC observed that money from the CMPFO was invested in the debentures of DHFL despite its "ill reputation".

The committee had observed there has been "critical irregularity" on part of the Ministry of Coal to oversee the functioning of CMPFO which led to the failure to ensure safety of its investments due to "lackadaisical approach in redeeming debentures of DHFL despite adverse critical ratings."

"The funds are not being diverted to the pensioners. We are the worst sufferers," Rao said.

In 2015, petitioners, under the banner of Federation of Coal Industries Retired Employees Association, had approached the Delhi high court regarding the valuation and revision of the Coal Mines Pension Scheme.

According to the petitioners, the pension fund grew from Rs 21,033.27 crore in 2022-23 to Rs 22,898.90 crore in 2023-24, and stood at Rs 24,495.66 crore as of March 31, 2025.

Despite an apparent monetarily healthy position, they argued, the members of the pension fund are drawing a very meagre amount of pension due to non-revision at the end of the Board and the Union government.

The matter is expected to be listed before the Delhi high court on March 20.

Meanwhile, coal pensioners have decided to stage a *dharna* at Jantar Mantar in New Delhi on March 30 to raise their demands.

The protest is being organised by AIACE-AICPA and other pensioners' organisations. Ahead of the protest, Rathor said that the government should recognise the sacrifices of coal workers and take immediate action to resolve the long-pending pension issue, emphasising the need to draw national attention to the difficult conditions faced by thousands of elderly coal pensioners.

संघर्ष से सिद्धि

हिन्दी दैनिक

संघर्ष से सिद्धि

खबरों के साथ, हर नज़रिये की बात

Sangharshsesiddhi@gmail.com

उज्जैन, रविवार 15 मार्च 2026

अंक-04 अंक-219

पृष्ठ-08, मूल्य-01 रुपये

"सर्वदली अल्पराज्य, राष्ट्र को इकितराती बनाओ"

कोल पेंशनरों को अब तक नहीं मिला वेतन समझौता और पेंशन वृद्धि का लाभ, 30 मार्च को जंतर-मंतर में होगा विशाल धरना

बैतूल चौफ राकेश सिंह
8226096301

बैतूल। कोल माईंस सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ (एचएमएस) की बैठक में कोल पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार एवं संबंधित प्रबंधन के प्रति नाराजगी जताई गई।

बैठक में बक्तारों ने कहा कि वर्ष 2018 से 2023 तक के वेतन समझौता क्रमांक-11 के एरिया और पेंशन वृद्धि का लाभ अब तक पेंशनरों को नहीं मिल पाया है, जबकि भारत सरकार द्वारा राजपत्र जारी हुए दो से तीन वर्षों का समय बीत चुका है।

बैठक में बताया गया कि जिन पेंशनरों को एक हजार रुपये से कम मासिक पेंशन मिल रही है, उन्हें प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन देने का प्रावधान वर्ष 2023-24 में भारत सरकार के राजपत्र में अधोदित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पश्चाच्छेत्र के पेंशनरों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इससे पेंशनरों में भारी असंतोष है।

बैठक में लोक लेखा समिति की 18 मार्च 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। साथ ही

सीएमपीएफ 1998 पेंशन योजना में संशोधन कर पेंशन रिवीजन और वृद्धि की मांग को लेकर वर्ष 2019 से जंतर-मंतर

बैठक में भारत सरकार से कोल पेंशनरों की पेंशन वृद्धि कर शीघ्र रिवीजन करने तथा पेंशनरों, स्टाफ और



नई दिल्ली सहित बनारस, धनबाद और कोलकाता में धरना-प्रदर्शन किए जाने की जानकारी दी गई। इसके बावजूद देशभर के लगभग छह लाख कोल पेंशनरों की मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

बैठक में यह भी कहा गया कि बैतूल जिले के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उर्दके को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन जिले के लगभग पचास हजार पेंशनरों की मांगों को लेकर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है।

कर्मचारियों को दो हजार रुपये प्रतिमाह डोमेस्टिक मॉडकल अलाउंस देने की मांग की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अर्जल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पी.के. सिंह राट्टेड़ के आग्रह पर 30 मार्च को जंतर-मंतर नई दिल्ली में होने वाले विशाल धरना-प्रदर्शन में बैतूल जिले से लगभग 40 से 50 सदस्य भाग लेंगे। बैठक में अध्यक्ष डी.के. साहू, महामंत्री डी.आर. इरबडे सहित अनेक सदस्य उपस्थित।

संघर्ष से सिद्धि का नारा, हर नज़रिये की बात

हिन्दी डीजल

संघर्ष से सिद्धि

संघर्ष से सिद्धि का नारा, हर नज़रिये की बात

SangharshseSiddhi@gmail.com | 15 अप्रैल, 2026 | पृष्ठ-04, पृष्ठ-01 पर | "सिद्धि से आता है, संघर्ष से नहीं आता।"

कोल पेंशनरों को अब तक नहीं मिला वेतन समझौता और पेंशन वृद्धि का लाभ, 30 मार्च को जंतर-मंतर में होगा विशाल धरना

अधुने चौक रावेन्द्रा सिंह
8326096301

बैंगलूर। कोल माइंस सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ (एचएएमएस) की बैठक में कोल पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार एवं संबंधित प्रबंधन के प्रति नाराजगी जताई गई।

बैठक में बतलाया गया कि वर्ष 2018 से 2023 तक के वेतन समझौता क्रमशः- 11 के एचएएमएस और पेंशन वृद्धि का लाभ अब तक पेंशनरों को नहीं मिल पाया है, जबकि भारत सरकार द्वारा राजपत्र जारी हुए दो से तीन वर्षों का समय खीट चुका है।

बैठक में बताया गया कि जिन पेंशनरों को एक हजार रुपये से कम मासिक पेंशन मिल रही है, उन्हें प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन देने का प्रावधान वर्ष 2023-24 में भारत सरकार के राजपत्र में अधीनस्थ किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बैंगलूर कोलपरीएक्स लिमिटेड पांचासों कोल पेंशनरों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। इससे पेंशनरों में भारी असंतोष है।

बैठक में लोक लेखा समिति की 18 मार्च 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। साथ ही

सोवियतक 1998 पेंशन योजना में संशोधन कर पेंशन रिजोनिंग और वृद्धि को मांग को लेकर वर्ष 2019 से जंतर-मंतर

बैठक में भारत सरकार से कोल पेंशनरों की पेंशन वृद्धि कर शीघ्र निर्धारित करने तथा पेंशनरों, स्टॉफ और



नई दिल्ली स्टॉल बनवास, भ्रष्टाचार और कोलाहल में भ्रष्टा-इंटरन किए जाने की जानकारी दी गई। इसके बावजूद देशभर के लगभग छह लाख कोल पेंशनरों की मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

बैठक में यह भी कहा गया कि बैंगलूर जिले के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री दुर्गादेव जॉर्ज को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन जिले के लगभग पचास हजार पेंशनरों की मांगों को लेकर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो सका है।

कर्मचारियों को दो हजार रुपये प्रतिमाह टेलिफोनिक मेंडेशन अलाउंस देने की मांग की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अंतर्गत कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के संघेयक पी.के. सिंह राठी के आह्वान पर 30 मार्च को जंतर-मंतर नई दिल्ली में होने वाले विशाल भारत-इंटरन में बैंगलूर जिले से लगभग 40 से 50 सदस्य भाग लेंगे। बैठक में अलाउंस डी.के. राठौड़, महामंत्री टी.आर. इरवडे, सचिव अनेक सदस्य उपस्थित।

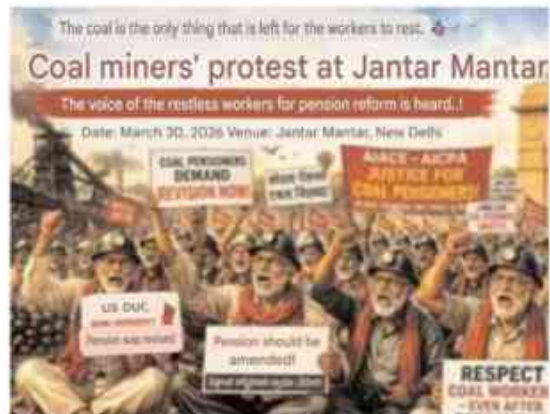
The voices of coal pensioners fighting for pensions, will resonate at Jantar Mantar

AICPA/AIACE convener P.K. Singh Rathore has called for a massive dharna on March 30.

Mancherial, 22, March (Praja Jyoti) The flames of the movement are burning once again for the rights of pensioners who have served the coal sector throughout their lives. All India Coal Pensioners Association (AICPA) and All India Coal Executives Association (AIACE) convener P.K. Singh Rathore announced that a huge dharna will be organized at Jantar Mantar in New Delhi on March 30, 2026 for pension revision. He emotionally stated that justice should be done to the pensioners who have worked hard in the coal sector for decades and that pension revision is essential for their life security. In this context, he called on coal pensioners, their family members, currently working executives and employees from across the country to participate in large numbers and make this dharna a success. "This is not just a dharna, It is a fight for our rights," he clarified. He suggested that everyone should play their part in this movement and spread the movement more widely through photos and videos. Don't surrender to old age Solidarity dharna from home P.K. Singh Rathore called on pensioners who cannot go to Jantar Mantar due to old age, illness or other reasons to also participate in this struggle. From 10 am to 1 pm, sit with family members in their homes or nearby places and raise slogans.



He suggested holding a solidarity dharna. "Our voice should be heard from anywhere. Our unity is our strength," he said. He expressed hope that if there is a response like this across the country, the government will be in a position to take a decision on the pension revision soon.



<https://www.coalnewsnetwork.com/pension-of-75-former-chairman-cmd-and-directors-appealed-to-pm/>

पेंशन :- 75 पूर्व चेयरमैन,सीएमडी,निदेशकों ने पीएम से लगाई गुहार

by Coal News Network

March 23, 2026

धनवाद :-कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन,निदेशक, सहायक कंपनियों के पूर्व सीएमडी,निदेशक एवं सिंगरेनी के पूर्व समेत 75 अधिकारियों ने पीएम से कोल पेंशन में सुधार का आग्रह किया है।75 पूर्व कोल अधिकारियों ने आज 23 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र दिया है।पत्र में कोल अधिकारियों ने पीएम से यह आग्रह किया है कि :- 1.कोयला पेंशन में संशोधन किया जाए,2.महंगाई से जुड़े समय समय पर समायोजन किया जाए,3.CMPS 98 के अंतर्गत किए अंशदान पर उचित रिटर्न सुनिश्चित किया जाए, 4.सेवानिवृत्त कोयला कर्मचारियों की गरिमा एवं वित्तीय सुरक्षा को बहाल किया जाए।

पत्र में कहा गया है कि लगभग 5 लाख सेवानिवृत्त कोयला कर्मियों की ओर से, हम आपके समक्ष विनम्रतापूर्वक एक भावपूर्ण एवं गंभीर अपील प्रस्तुत करते हैं कि सेवानिवृत्त कोयला कर्मचारियों की पेंशन संशोधन की लंबे समय से लंबित मांग पर आवश्यक आदेश जारी किए जाएं। समस्या की जड़ यह है कि सेवानिवृत्ति की तिथि पर निर्धारित पेंशन, मूल्य वृद्धि के अनुसार किसी भी प्रकार के समायोजन के बिना, स्थिर बनी रहती है। “यही सेवानिवृत्त कर्मी, जिन्होंने राष्ट्र की उन्नति में अपना जीवन समर्पित किया, बढ़ती महंगाई, दवायों और मूलभूत आवश्यकताओं के कारण असंगत हो चुकी पेंशन पर जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।”

यह अत्यंत चिंताजनक है कि कोयला क्षेत्र की पेंशन योजना के अंतर्गत कोष प्रबंधन में त्रुटियों और कमजोर निवेश निर्णयों के कारण प्रभावित हुई है। [3] कमियों को की 12वीं रिपोर्ट (रिपोर्ट संख्या 2193, दिनांक 18 मार्च 2020) में भी रेखांकित किया गया है। यद्यपि सरकार ने योजना की समीक्षा एवं पुनर्गठन पर सहमति व्यक्त की थी, फिर भी कोई सार्थक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है।

हम सरकार से दृढ़तापूर्वक अनुरोध करते हैं कि कोयला पेंशन में पर्याप्त वृद्धि के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, ताकि सेवानिवृत्त खनिक एवं कर्मचारी अपने शेष जीवन को सम्मान और सुरक्षा के साथ व्यतीत कर सकें। यह न्याय, गरिमा और उन लोगों के प्रति राष्ट्रीय कृतज्ञता का विषय है, जिन्होंने धरती के नीचे रहकर देश की अर्थव्यवस्था को चलायमान रखा। हम (AIACE) एवं (AICPA) द्वारा संचालित शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति अपना पूर्ण समर्थन एवं एकजुटता भी व्यक्त करते हैं, जो कोयला पेंशनरों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

[4]ने किया है पत्र पर हस्ताक्षर :-पूर्व चेयरमैन : एमके चौधरी,पीके सेनगुप्ता, पीएस भट्टाचार्य, एनसी झा,एके झा, पूर्व सीएमडी :- ए कलाम,आरपी रिटोलिया, बीके सिन्हा, एस चक्रवर्ती, एसआर उपाध्याय, एमपी दीक्षित, आरके साहा, टीके लाहड़ी,ए एन सहाय, एके देवनाथ,टीके नाग,ओमप्रकाश, आर आर मिश्रा, शेखर शरण, पीके सिन्हा, बीएन शुक्ला, मनोज कुमार, मनोज कुमार,भोला सिंह,जेपी द्विवेदी,समेत अन्य निदेशक लोग शामिल हैं।

https://www.industrialpunch.com/former-cil-scccl-leadership-submits-appeal-to-prime-minister-seeking-urgent-pension-reform/#google_vignette

Former CIL & SCCL Leadership Submits Appeal to Prime Minister Seeking Urgent Pension Reform

The appeal, dated 23 March 2026, highlights the long-standing issue affecting nearly 5 lakh retired coal employees.

By

Industrial Punch

- 23 March 2026



A distinguished group of 75 members, consisting of former Chairmen, CMDs and Directors of Coal India Limited and Singareni Collieries Company Limited, has submitted an appeal to the Prime Minister, Narendra Modi, urging immediate and meaningful reform of coal pension.

The appeal was submitted with active efforts made by Onkar Singh, Executive Body member of All India Association of Coal Executives (AIACE) who, on behalf of the elite group, submitted this in person.

The appeal, dated 23 March 2026, highlights the long-standing issue affecting nearly 5 lakh retired coal employees, whose pensions-fixed at the time of

retirement-have remained stagnant without any linkage to inflation or rising cost of living. Coal industry in India holds a unique and critical position in meeting the nation's primary energy requirements. Unlike other industries, its sustainability depends heavily on scientific mining and conservation undertaken in the past by its employees.

The former senior leadership emphasized that India's coal sector, which contributes over 55% of the nation's commercial energy needs, has been built through decades of dedicated service under extremely hazardous and challenging conditions. They noted that these contributions have enabled the sector to generate over ₹70,000 crore annually for the national exchequer.

The representation also draws attention to serious concerns regarding the Coal Mines Pension Scheme, 1998 (CMPS-1998), including issues of corpus management and suboptimal investment decisions. These concerns were earlier highlighted in the 12th Report of the Public Accounts Committee (2020), yet remain largely unaddressed.

The signatories have urged the Government of India to:

- Undertake immediate revision of coal pension
- Introduce a mechanism for periodic adjustment linked to inflation
- Ensure fair returns on contributions under CMPS-1998
- Restore dignity and financial security for retired coal employees

The appeal underscores that coal pensioners are not seeking any favour, but only the rightful realization of benefits assured under the pension scheme.

The team of old veterans of coal industry, retd. Chairmen, CMDs, Directors of Coal India Ltd and Singareni Collieries Company Ltd have also reiterated their full support to the peaceful movement led by All India Association of Coal Executives (AIACE) and All India Coal Pensioners Association (AICPA) for justice to coal pensioners.

AIACE and AICPA expressed confidence that the Hon'ble Prime Minister will take a sympathetic and time-bound decision to address this long-pending issue of national importance.

24 March, 2026

Dhanbad-Asansol Edition



दैनिक भास्कर

कोयला क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में संशोधन की मांग

कोयला क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में संशोधन की मांग को लेकर कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन व निदेशकों के 75 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील की है।

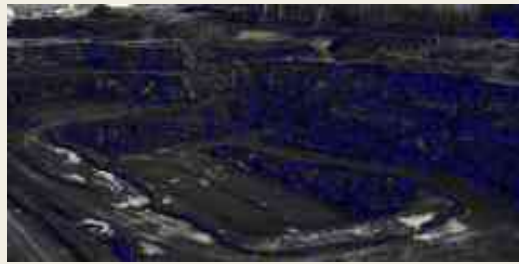
भेजी गई इस अपील में कहा गया है कि कोयला क्षेत्र के लगभग 5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्षों से पेंशन संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति के समय तय की गई पेंशन आज भी बिना किसी महंगाई समायोजन के जस की तस बनी हुई है, जिससे पेंशनभोगियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

पूर्व अधिकारियों ने कहा कि देश की 55 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में कोयला क्षेत्र की अहम भूमिका है और यह राष्ट्रीय खजाने में प्रतिवर्ष 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान देता है। इसके बावजूद इस क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मियों को पर्याप्त पेंशन नहीं मिल पा रही है।

<https://thewire.in/rights/spent-our-lives-serving-the-nation-ex-coal-mine-employees-write-to-modi-over-pension-revision>

‘Spent Our Lives Serving the Nation’: Ex-Coal Mine Employees

Write to Modi Over Pension Revision



Sharmita Kar

24/Mar/2026

The pensioners have alleged that for decades, they have worked in some of the harshest and most hazardous conditions. Yet, they are now struggling to survive because the pension rates have fallen far behind the rising costs of living, medicines and basic necessities.

Representative image of a coal mine. Photo: Lachlan/Unsplash

New Delhi: Seventy-five retired coal mine employees, consisting of former chairmen, managing directors and directors of Coal India Limited and Singareni Collieries Company Limited, on Monday (March 23) wrote to prime minister Narendra Modi, urging him to address the issue of long pending pension revision, which they have repeatedly raised has remained unchanged without any revision since their retirement.

“We have superannuated from Coal India Ltd. (CIL) / its Subsidiary Companies and Singareni Collieries Company Ltd. (SCCL), after serving the nation for decades, many of us at the level of Chairman and Directors. Our collective efforts, along with lakhs of coal workers, have helped build these institutions into pillars of India’s energy security, contributing over 55% of the country’s commercial energy needs and generating more than Ra 70,000 crores annually for the national exchequer,” read a letter, dated March 23, 2026.

“The root of the problem is the fact that the pension fixed on the date of retirement, remains constant forever without any adjustment for rise in prices,” they said.

The retirement age for coal mine employees is 60 years. Many of the protesting pensioners are in the age bracket of 70-90 years now, facing serious health problems and struggling to meet daily expenses.

The Wire has previously [reported](#) that several top-level executives of these coal companies receive a pension of less than Rs 10,000 per month. The pension amount which, as per the Coal Mines Pension Scheme (CMPS), 1998, is to be reviewed every three years has not been revised for many employees since inception. Additionally, the 1998, 2007 and 2017 wage revisions for employees were also not applied to these pensioners.

The pensioners have alleged that for decades, they have worked in some of the harshest and most hazardous conditions, “comparable only to those of jawans in the armed forces, to power the nation’s growth and ensure energy security”. Yet, many of these retired workers are now struggling to survive because the pension rates have fallen far behind the rising costs of living, medicines and basic necessities.

“It is deeply concerning that pension in coal sector under CMPS-1998 has suffered due to corpus mismanagement and suboptimal investment decisions. These shortcomings have already been highlighted in the 12th Report of the Public Accounts Committee (Report No. 2193, presented on 18th March 2020). Though the Government had agreed to review and restructure the scheme, no meaningful corrective action has followed,” they have said.

The Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO), the autonomous body which provides for the pension of coal sector employees, and falls under the Union coal ministry, has repeatedly told the pensioners that their pensions have not been revised due to a shortage of funds.

In October 2025, 77 years after the 1948 Act’s enactment, the Union government announced an overhaul by proposing a draft Bill, titled the [Coal Mines Employees’ Provident Fund and Miscellaneous Bill, 2025](#).

The Bill has not been tabled in the parliament yet.

In March last year, Modi, hailing the country’s achievement of 1 billion tonne coal production, called it a “historic milestone” and “proud moment for India”, and [recognised](#) the relentless dedication and hard work of those associated with the sector.

Highlighting this, the coal pensioners said that the “entire Coal Family of India felt proud” when this was declared. “Such proud moments are because of the dedication of today’s

workforce in coal (tomorrow's pensioners) and equally the contribution of the past workforce (today's pensioners)."

The pensioners have demanded the government to take immediate steps to substantially increase the coal pension so that retired miners and employees can "live their remaining years with dignity and security".

"It is an issue of justice, dignity, and national gratitude to those who spent their lives serving the nation from beneath the earth to keep the wheels of the economy running," they said.

They have also demanded the government to introduce a mechanism for periodic adjustment linked to inflation, ensure fair returns on contributions under CMPS-1998 and restore dignity and financial security for retired coal employees. Separately, they have also demanded that medical facilities be provided free of cost to retired employees and their spouses.

Notably, the All India Association of Coal Executives (AIACE) and the All India Coal Pensioners Association (AICPA) have been raising these demands for years.

"It is a matter of grave concern that while the coal sector – particularly Coal India Limited and Singareni Collieries Company Limited – has consistently contributed thousands of crores of rupees to the national exchequer in the form of taxes, royalties, and dividends, the very workforce that built and sustained this sector has been left neglected in their old age," the associations said in a letter on Monday to Securities and Exchange Board of India, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange of India.

The coal pensioners, led by AIACE and AICPA, have decided to stage a *dharna* at Jantar Mantar in New Delhi on March 30 to raise their demands.

सम्पादकीय

नई दिल्ली में 30 मार्च को धरना देंगे कोयला पेंशनर, पेंशन वृद्धि की मांग तेज

सीटिया फौर न्यू

खराबामी, कोयला पेंशनरों को पेंशन वृद्धि को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज होने जा रहा है। अखिल इंडिया एमोमिआरान और कोयला एजोम्युटिव (अखिल भारतीय कोयला कार्यकारी संघ) और अखिल इंडिया एमोमिआरान और कोयला पेंशनर (अखिल भारतीय कोयला पेंशनर संघ) को संयुक्त आन्दोलन के तहत 23 मार्च को आगोजिब को घंट, जियम सार्वममति से आंदोलन पुनः शुरु करदे का निर्णय लिया गया बैठक में सदस्यों ने कोयला खान अधिकतम निधि अधिनियम, 1948 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को संघट में शीघ्र प्रस्तुत करने की मांग उठाई। यभाओ ने कहा कि पेंशन पेंशनरों का अधिकार है और कोयला खान प्रोडिक्ट फंड अधिनियम (कोयला खान अधिकतम निधि संगठन) केअल क्षेत्र का संरक्षक है, इसलिए पेंशन वृद्धि पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए संयुक्त बैठक में का भी निर्णय लिया गया कि 30 मार्च को नई



दिल्ली में एक उपरान अधिऑल किया जाएगा। इस दौरान केडीएल इमिक संगठनों तक कोयला इंडिया लिमिटेड (कोयला इंडिया लिमिटेड) और इमरनेओ कोयलापरीत कंपनी लिमिटेड (इमरनेओ कोयलापरीत कंपनी लिमिटेड) के अन्य संगठनों से भी आंदोलन के समर्थन के लिए संपर्क किया जाएगा संयोजक पी.के. गिां गरी ने कहा कि यदि पेंशन में वृद्धि संभव नहीं होती है

तो पेंशन क्षेत्र की सभी पेंशनरों को धरना भी जारी रहिए। उन्होंने केडी सरकार, कोयला इंडिया लिमिटेड और कोयला खान अधिकतम निधि संगठन से अपील की कि वे कोयला पेंशनरों को जनज सार्थ पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करें संघों ने स्पष्ट किया है कि यदि सार्थ पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और अधिक गंवारक और अडडगलाक का दिना जाएगा

If a former Singareni employee dies, widow's pension should be granted immediately

- As per the new PPOs, banks should pay widow pension immediately, despite Dhanbad orders, widows are not implementing it, says Arighosh

Mancherial, 25th March (Praja Jyoti): Nationwide delay in granting widow pension to the life partners of K coal mine pensioners after their death is a matter of great concern. The same situation continues in Singareni area as well, causing financial and mental hardship to the widows. As per the rules, immediately after the death of a retired employee, the pension account should be converted to 'Former Survivor Mode' without any delay in the payment of family pension to his wife. For this, the Aadhaar, PAN cards and Pension Payment Order (PPO) copies of the wife and husband have to be submitted to the Coal Mines Provident Fund (CMPF). As part of this process, the pension available to the wife (usually 60 percent) is clearly mentioned in the revised PPO. In case of sudden death of a retired employee, after getting the revised PPO, the concerned widow should submit the death

certificate, Aadhaar, PAN and bank passbook copies along with the PPO copies to the SBI branch manager in his/her residential area. The bank officials sent the documents to the nodal bank in Dhanbad and



Family pension should be granted within a month. However, there are allegations that this policy is not being implemented in real situations. An example of this is K. Muralikrishnam Raju (: 577156/22),

who retired from Singareni Srirampur Workshop, who

(died on November 18, 2025. Late)

his wife K. Lakshmi submitted the necessary documents at the Medipalli SBI branch in Hyderabad on December 4, but even after three months, the family pension was not granted. This matter was brought to the attention of All India Coal Pensioners Association Convener P.K. Singh Rathore, who appealed to the officials of the Ministry of Coal, Singareni CMD, CMPF Commissioner Dhanbad, Grievance Cell and Nodal Bank through email. Singareni Retired Employees Welfare Association General Secretary Alavandar Venumathay, President Dandamraju Ramachandra Rao, and Mancherial District Honorary President of the Retired Employees' Association Rallabandi Rajanna said that widows are facing serious difficulties as many such cases remain unsolved. They urged the government to immediately resolve all pending cases and grant widow pension.

Dharna at Jantar Mantar for pension hike for coal pensioners

AICPA seeks support from members of Parliament

Mancherial, 25 March (Praja Jyoti): Coal across the country The All India Coal Pensioners Association (AICPA) has urged the central government to immediately increase the pension of retired workers who have served the sector. To this end, a petition has been sent to the Lok Sabha and Rajya Sabha members, requesting them to support the dharna they will organize at Jantar Mantar. AICPA convener P.K. Singh Rathore gave these details. He said that currently coal pensioners are getting only a pension of Rs 1,000 to Rs 3,000 per month, which is not enough in the face of rising inflation and medical expenses. He expressed his concern that old-age pensioners are facing serious difficulties due to this. Although the Public Accounts Committee of Parliament had already identified shortcomings in the coal pension system in 2020 and suggested amendments, the association criticized the government for not taking any action so far. In this context, AICP has announced that it will hold a one-day dharna at Jantar Mantar in New Delhi on the 30th of this month for a pension hike.



announced. It requested the members of Parliament to attend and support this program. It appealed to the MPs to raise the pension issue in Parliament, stand united with the pensioners, and participate in the dharna program to strengthen their voice. AICPA Convener P.K. Singh Rathore appealed that it is the responsibility of the government to provide a dignified life to the coal workers who have served the country for many years, and to take immediate action on the pension hike.

https://www.business-standard.com/industry/news/top-brass-of-cil-sccl-look-for-pm-intervention-for-retired-employees-pension-revision-126032400913_1.html

Ex-Coal India top brass seek PM Modi's help to revise stagnant pensions

In the March 23 letter, the former top executives said the pension fixed at the time of retirement remains "constant forever without any adjustment for rise in prices"

Coal India

Press Trust of India **Kolkata**

Several former top brass of Coal India Ltd (CIL), its subsidiaries and Singareni Collieries Company Ltd have sought Prime Minister Narendra Modi's intervention to revise retired employees' pension, pointing out that it "remains constant forever".

Former CIL director (technical) Binay Dayal, a signatory of the letter, on Tuesday said 75 former chairpersons, managing directors and directors of the PSUs have written to the prime minister over the issue.

In the March 23 letter, the former top executives said the pension fixed at the time of retirement remains "constant forever without any adjustment for rise in prices", leaving many retired miners struggling.

They alleged mismanagement of the Coal Mines Pension Scheme (CMPS)-1998 corpus and suboptimal investment decisions as the root cause of the pension amount remaining static, pointing out that the Public Accounts Committee had highlighted these shortcomings in its 12th report.

Despite the government's stated commitment to review and restructure the scheme, no corrective action had followed, the letter claimed.

The former executives noted that CIL and Singareni Collieries Company Ltd (SCCL) together meet over 55 per cent of the country's commercial energy needs and generate more than ₹70,000 crore annually for the national exchequer.

"Coal pensioners are not seeking charity or sympathy. They are only requesting restoration of their rightful dues -- fair returns on their own contributions as assured under the CMPS-1998 scheme, which unfortunately remains unfulfilled," said P K Singh Rathor, the convenor of All India Association of Coal Executives (AIACE) and the All India Coal Pensioners Association (AICPA).

The signatories include five former CIL chairpersons -- S K Chowdhary, Prasenjit Kumar Sen Gupta, Partha S Bhattacharyya, Nirmal Chandra Jha and Anil Kumar Jha -- former CMDs of subsidiary companies, and directors across technical, finance, personnel and marketing functions.

<https://assets.thehansindia.com/telangana/retired-coal-workers-to-protest-at-jantar-mantar-demanding-pension-hike-1055264#>

Retired coal workers to protest at Jantar Mantar demanding pension hike

By The Hans India

National demonstration set for March 30 as retirees highlight struggles with stagnant payments and rising costs of essential living expenses

Retired coal workers from across India are preparing to hold a peaceful protest at Jantar Mantar in New Delhi on March 30. They are demanding an immediate and substantial increase in coal pensions under the Coal Mines Pension Scheme. The demonstration is being organised by the All India Association of Coal Executives, the All India Coal Pensioners Association and other representative organisations.

For decades, these workers toiled under extremely difficult and hazardous conditions in underground mines, contributing significantly to the nation's energy security and industrial growth. However, many retired individuals now subsist on meagre pensions that have remained largely stagnant despite the rising costs of food, medicine and other essentials.

Organisers stated that current pension rates are insufficient to provide a dignified life for elderly pensioners and their families. Many retirees, aged between 60 and 90, face serious health issues and struggle to meet daily expenses without adequate support. Their key demands include a substantial hike in coal pensions, linking these payments to inflation and ensuring long-term financial security for the community.

Speaking ahead of the protest, PK Singh Rathor, Convenor of AICPA and AIACE, said the government must recognise the sacrifices of coal workers and take immediate action to resolve this long-standing issue. He emphasised that the protest aims to draw national attention to the hardships faced by thousands of elderly coal pensioners who feel abandoned by current policies.

Representatives from several coal-producing states are expected to participate, urging the Government of India and relevant authorities to implement immediate welfare measures.

https://www.industrialpunch.com/former-cil-sccl-leadership-submits-appeal-to-prime-minister-seeking-urgent-pension-reform/#google_vignette

Former CIL & SCCL Leadership Submits Appeal to Prime Minister Seeking Urgent Pension Reform

The appeal, dated 23 March 2026, highlights the long-standing issue affecting nearly 5 lakh retired coal employees.

By

Industrial Punch

- 23 March 2026



A distinguished group of 75 members, consisting of former Chairmen, CMDs and Directors of Coal India Limited and Singareni Collieries Company Limited, has submitted an appeal to the Prime Minister, Narendra Modi, urging immediate and meaningful reform of coal pension.

The appeal was submitted with active efforts made by Onkar Singh, Executive Body member of All India Association of Coal Executives (AIACE) who, on behalf of the elite group, submitted this in person.

The appeal, dated 23 March 2026, highlights the long-standing issue affecting nearly 5 lakh retired coal employees, whose pensions-fixed at the time of

retirement-have remained stagnant without any linkage to inflation or rising cost of living. Coal industry in India holds a unique and critical position in meeting the nation's primary energy requirements. Unlike other industries, its sustainability depends heavily on scientific mining and conservation undertaken in the past by its employees.

The former senior leadership emphasized that India's coal sector, which contributes over 55% of the nation's commercial energy needs, has been built through decades of dedicated service under extremely hazardous and challenging conditions. They noted that these contributions have enabled the sector to generate over ₹70,000 crore annually for the national exchequer.

The representation also draws attention to serious concerns regarding the Coal Mines Pension Scheme, 1998 (CMPS-1998), including issues of corpus management and suboptimal investment decisions. These concerns were earlier highlighted in the 12th Report of the Public Accounts Committee (2020), yet remain largely unaddressed.

The signatories have urged the Government of India to:

- Undertake immediate revision of coal pension
- Introduce a mechanism for periodic adjustment linked to inflation
- Ensure fair returns on contributions under CMPS-1998
- Restore dignity and financial security for retired coal employees

The appeal underscores that coal pensioners are not seeking any favour, but only the rightful realization of benefits assured under the pension scheme.

The team of old veterans of coal industry, retd. Chairmen, CMDs, Directors of Coal India Ltd and Singareni Collieries Company Ltd have also reiterated their full support to the peaceful movement led by All India Association of Coal Executives (AIACE) and All India Coal Pensioners Association (AICPA) for justice to coal pensioners.

AIACE and AICPA expressed confidence that the Hon'ble Prime Minister will take a sympathetic and time-bound decision to address this long-pending issue of national importance.

<https://money.rediff.com/news/market/coal-pension-revision-ex-cil-brass-seek-pm-intervention/44112720260324>

Coal Pension Revision: Ex-CIL Brass Seek PM Intervention

By **Rediff Money Desk, Kolkata**

1 Minute Read Listen to Article

Share:

Mar 24, 2026 17:19

75 ex-CIL & SCCL executives urge PM Modi to revise retired coal employees' pension, citing mismanagement & static pension amounts.



Photograph: Amit Dave/Reuters

Kolkata, Mar 24 (PTI) Several former top brass of Coal India Ltd (CIL), its subsidiaries and Singareni Collieries Company Ltd have sought Prime Minister Narendra Modi's intervention to revise retired employees' pension, pointing out that it "remains constant forever".

Former CIL director (technical) Binay Dayal, a signatory of the letter, on

Tuesday said 75 former chairpersons, managing directors and directors of the PSUs have written to the prime minister over the issue.

In the March 23 letter, the former top executives said the pension fixed at the time of retirement remains "constant forever without any adjustment for rise in prices", leaving many retired miners struggling.

They alleged mismanagement of the Coal Mines Pension Scheme (CMPS)-1998 corpus and suboptimal investment decisions as the root cause of the pension amount remaining static, pointing out that the Public Accounts Committee had highlighted these shortcomings in its 12th report.

Despite the government's stated commitment to review and restructure the scheme, no corrective action had followed, the letter claimed.

The former executives noted that CIL and Singareni Collieries Company Ltd (SCCL) together meet over 55 per cent of the country's commercial energy needs and generate more than Rs 70,000 crore annually for the national exchequer.

"Coal pensioners are not seeking charity or sympathy. They are only requesting restoration of their rightful dues – fair returns on their own contributions as assured under the CMPS-1998 scheme, which unfortunately remains unfulfilled," said P K Singh Rathor, the convenor of All India Association of Coal Executives (AIACE) and the All India Coal Pensioners Association (AICPA).

The signatories include five former CIL chairpersons – S K Chowdhary, Prasenjit Kumar Sen Gupta, Partha S Bhattacharyya, Nirmal Chandra Jha and Anil Kumar Jha – former CMDs of subsidiary companies, and directors across technical, finance, personnel and marketing functions.

Source: **PTI** By **Rediff Money Desk, Kolkata**

<https://www.coalnewsnetwork.com/pension-of-75-former-chairman-cmd-and-directors-appealed-to-pm/>

पेंशन :- 75 पूर्व चेयरमैन,सीएमडी,निदेशकों ने पीएम से लगाई गुहार

by [Coal News Network](#)

March 23, 2026

धनबाद :-कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन,निदेशक, सहायक कंपनियों के पूर्व सीएमडी,निदेशक एवं सिंगरेनी के पूर्व समेत 75 अधिकारियों ने पीएम से कोल पेंशन में सुधार का आग्रह किया है।75 पूर्व कोल अधिकारियों ने आज 23 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र दिया है।पत्र में कोल अधिकारियों ने पीएम से यह आग्रह किया है कि :- 1.कोयला पेंशन में संशोधन किया जाए,2.महंगाई से जुड़े समय समय पर समायोजन किया जाए,3.CMPS 98 के अंतर्गत किए अंशदान पर उचित रिटर्न सुनिश्चित किया जाए, 4.सेवानिवृत्त कोयला कर्मचारियों की गरिमा एवं वित्तीय सुरक्षा को बहाल किया जाए।

पत्र में कहा गया है कि लगभग 5 लाख सेवानिवृत्त कोयला कर्मियों की ओर से, हम आपके समक्ष विनम्रतापूर्वक एक भावपूर्ण एवं गंभीर अपील प्रस्तुत करते हैं कि सेवानिवृत्त कोयला कर्मचारियों की पेंशन संशोधन की लंबे समय से लंबित मांग पर आवश्यक आदेश जारी किए जाएं। समस्या की जड़ यह है कि सेवानिवृत्त की तिथि पर निर्धारित पेंशन, मूल्य वृद्धि के अनुसार किसी भी प्रकार के समायोजन के बिना, स्थिर बनी रहती है। “यही सेवानिवृत्त कर्मी, जिन्होंने राष्ट्र की उन्नति में अपना जीवन समर्पित किया, बढ़ती महंगाई, दवायियों और मूलभूत आवश्यकताओं के कारण असंगत हो चुकी पेंशन पर जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।”

यह अत्यंत चिंताजनक है कि कोयला क्षेत्र की पेंशन योजना के अंतर्गत कोष प्रबंधन में त्रुटियों और कमजोर निवेश निर्णयों के कारण प्रभावित हुई है। [3] कमियों को की 12वीं रिपोर्ट (रिपोर्ट संख्या 2193, दिनांक 18 मार्च 2020) में भी रेखांकित किया गया है। यद्यपि सरकार ने योजना की समीक्षा एवं पुनर्गठन पर सहमति व्यक्त की थी, फिर भी कोई सार्थक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है।

हम सरकार से दृढ़तापूर्वक अनुरोध करते हैं कि कोयला पेंशन में पर्याप्त वृद्धि के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, ताकि सेवानिवृत्त खनिक एवं कर्मचारी अपने शेष जीवन को सम्मान और सुरक्षा के साथ व्यतीत कर सकें। यह न्याय, गरिमा और उन लोगों के प्रति राष्ट्रीय कृतज्ञता का विषय है, जिन्होंने धरती के नीचे रहकर देश की अर्थव्यवस्था को चलायमान रखा। हम (AIACE) एवं (AICPA) द्वारा संचालित शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति अपना पूर्ण समर्थन एवं एकजुटता भी व्यक्त करते हैं, जो कोयला पेंशनरों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

[3]ने किया है पत्र पर हस्ताक्षर :-पूर्व चेयरमैन : इसके चौधरी,पीके सेनगुप्ता, पीएस भट्टाचार्य, एनसी झा,एके झा, पूर्व सीएमडी :- ए कलाम,आरपी रिटोलिया, बीके सिन्हा, एस चक्रवर्ती, एसआर उपाध्याय, एमपी दीक्षित, आरके साहा, टीके लाहड़ी,ए एन सहाय, एके देवनाथ,टीके नाग,ओमप्रकाश, आर आर मिश्रा, शेखर शरण, पीके सिन्हा, बीएन शुक्ला, मनोज कुमार, मनोज कुमार,भोला सिंह,जेपी द्विवेदी,समेत अन्य निदेशक लोग शामिल हैं।

75 ex-top brass of CIL, SCCL seek PM's intervention for retired employees' pension revision

PTI

24 March, 2026 05:47 pm IST

Former top executives from Coal India Ltd (CIL) and Singareni Collieries wrote to PM Modi, seeking revised pensions for retired employees. They highlighted that pensions remain constant, causing hardship, and alleged mismanagement of the Coal Mines Pension Scheme (CMPS)-1998 corpus. They urged intervention to restore their rightful dues as assured by the scheme.

Kolkata, Mar 24 (PTI) Several former top brass of Coal India Ltd (CIL), its subsidiaries and Singareni Collieries Company Ltd have sought Prime Minister Narendra Modi's intervention to revise retired employees' pension, pointing out that it "remains constant forever".

Former CIL director (technical) Binay Dayal, a signatory of the letter, on Tuesday said 75 former chairpersons, managing directors and directors of the PSUs have written to the prime minister over the issue.

In the March 23 letter, the former top executives said the pension fixed at the time of retirement remains "constant forever without any adjustment for rise in prices", leaving many retired miners struggling.

They alleged mismanagement of the Coal Mines Pension Scheme (CMPS)-1998 corpus and suboptimal investment decisions as the root cause of the pension amount remaining static, pointing out that the

Public Accounts Committee had highlighted these shortcomings in its 12th report.

Despite the government's stated commitment to review and restructure the scheme, no corrective action had followed, the letter claimed.

The former executives noted that CIL and Singareni Collieries Company Ltd (SCCL) together meet over 55 per cent of the country's commercial energy needs and generate more than Rs 70,000 crore annually for the national exchequer.

“Coal pensioners are not seeking charity or sympathy. They are only requesting restoration of their rightful dues – fair returns on their own contributions as assured under the CMPS-1998 scheme, which unfortunately remains unfulfilled,” said P K Singh Rathor, the convenor of All India Association of Coal Executives (AIACE) and the All India Coal Pensioners Association (AICPA).

The signatories include five former CIL chairpersons – S K Chowdhary, Prasenjit Kumar Sen Gupta, Partha S Bhattacharyya, Nirmal Chandra Jha and Anil Kumar Jha – former CMDs of subsidiary companies, and directors across technical, finance, personnel and marketing functions.

PTI BSM NSD

<https://thewire.in/rights/many-have-passed-away-waiting-retired-coal-workers-demand-pension-revision-pending-for-three-decades>

‘Many Have Passed Away Waiting’: Retired Coal Workers Demand Pension Revision Pending for Three Decades



Sharmita Kar

The pensioners, all of whom are now in the age bracket of 60-90 years, say that their pensions have never been revised despite a mandate to review the amount every three years.



Workers at the North Dadhu coal block in Jharkhand. Photo: PTI

New Delhi: Retired coal workers across the country are planning a fresh protest as their pensions have not been revised since the time of their retirement, with several top-level executives getting less than Rs 10,000 per month.

The retired employees – mainly from Singareni Collieries Company Limited (SCCL), Coal India Limited (CIL) and their subsidiary companies – have alleged that the pension amount which, as per the Coal Mines Pension Scheme, 1998, is to be reviewed every three years has not been revised since inception. Additionally, the 1998, 2007 and 2017 wage revisions for employees were also not applied to these pensioners.

“There are more than five lakh coal pensioners whose pensions have not been revised. Many have even passed away waiting,” said Venu Madhav, a retired SCCL employee, who has been advocating for pension revision for years.

While the government raised the minimum monthly pension rate in 2024 to Rs 1,000 for those getting even lesser, many mid-to-senior-level retired employees continue to receive meagre monthly pensions that have not kept pace with inflation.

SCCL and CIL are both public sector undertakings under the administrative control of the Union coal ministry. However, these pensioners have been overlooked despite the pensions of other central government employees **having been enhanced** from time to time as per the Unified Pension Scheme.

Similarly, the pension amount for employees of other public sector enterprises and public sector undertakings – like Gas Authority of India Ltd, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation and public sector banks – have also increased over the years.

The Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO), the autonomous body which provides for the pension of coal sector employees, and falls under the Union coal ministry, has repeatedly told the pensioners that due to a shortage of funds, they have not revised the pensions.

Pensioners have, however, countered this in a petition in the Delhi high court, stating that the fund has grown over the years.

‘Government not doing anything for us’

Rayanna P.B. worked at SCCL, Telangana for 33 years before retiring as the chief transport officer with a basic pay of Rs 40,000 in 2006. Seventy nine now, he gets a pension of Rs 8,087 per month, the same as 20 years ago.

“We work so hard for so many years, take risks on the job, inhale coal dust regularly, yet the government is not doing anything to improve our lives,” he alleged.

Ramachandra Reddy B., another SCCL retiree who retired as a general manager of civil operations in 2002, said, “I was on one of the higher pay brackets. Yet, my pension, which was Rs 4,000 at the time, has not been revised to date.”

In 2002, Reddy drew a basic pay of Rs 23,600, which he said was equivalent to nearly Rs 1 lakh, with the wage revisions for employees since. “What good is Rs 4,000 today to run daily expenses?” the 82-year-old asked.

Like him, Prabir Kumar Mukherjee, a retired CIL executive, who gets a monthly pension of Rs 9,977, said, “The basic pay of employees has increased over the years. The 2007 and 2017 wage revisions

provided for handsome revisions for newer employees, making way for better pensions too. However, for us, in 27 years, there has been no pension revision.”

“The Coal Mines Provident Fund Organisation keeps saying that they do not have funds and so cannot increase the pension rate. The government is taking no action in this regard,” Mukherjee said.

Madhav said, “The central government keeps talking about ‘*atmanirbharta*’, they ask us to be ‘*atmanirbhar*’, but how will we be if we remain so poor? So many industries are dependent on coal and coal workers – power supply being at the top. It is a dangerous job that we do, there are health risks involved. Yet, we are not given enough pension or benefits to even pay medical bills.”

A Bill yet to be tabled in the parliament

The retirement age for coal mine employees is 60 years. Many of the protesting pensioners are in the age bracket of 70-90 years now, facing serious health problems and struggling to meet daily expenses.

The Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948, was last amended in 1996. The Coal Mines Pension Scheme, which replaced the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971, came into effect on March 31, 1998, to provide monthly pension benefits to retired coal miners, and was covered under the 1948 Act.

In October 2025, 77 years after the 1948 Act’s enactment, and following years of protests by coal pensioners, the Union government announced an overhaul by proposing a draft Bill, titled the [Coal Mines Employees’ Provident Fund and Miscellaneous Bill, 2025](#).

The Bill has not been tabled in the parliament yet. In a letter to the coal ministry, dated October 15, 2025, the All India Association of Coal Executives (AIACE) and All India Coal Pensioners Association (AICPA), demanded restructuring of the pension scheme to include the pensioners’ demands – a substantial increase in coal pensions, linking pensions to inflation and ensuring financial security and dignity for retired coal workers who dedicated their lives to building the nation’s coal industry.

The associations also sought a timeline for the preparation and implementation of a new pension scheme under this Bill to ensure the introduction of a Dynamic Pension Scheme with built-in Dearness Relief (DR) linkage without requiring parliamentary amendment, as per the letter. DR is additional payment to pensioners to ensure the pay keeps up with inflation.

‘No dearness allowance’

The AIACE and AICPA has organised similar protests several times in the past too, including in 2019, 2022, 2023 and 2025.

Speaking to *The Wire*, P.K. Singh Rathor, convener of the AIACE-AICPA, said that in so many years, there was also no provision for dearness relief in the scheme. “As a result, even someone who retired at the top level may be getting something around Rs 3,000 because their pension was never revised,” he said.

In a supplementary letter, the coal employees’ body said, “In the 27 years since the pension scheme’s inception, no comprehensive revision or actuarial rebalancing has ever been implemented. The pension amount paid to retired coal employees is grossly inadequate – in many cases less than Rs 1,000 per month – rendering the scheme socially meaningless and financially exploitative.

“The Court case and representations for enhancement of pension over two decades show a complete failure of fiduciary responsibility and erosion of pensioners’ faith in the system,” the letter added.

When *The Wire* reached out to the coal ministry, it reverted with the standard response that the CMPFO “does not have sufficient funds to sustain an increase in pension”.

According to Chetna Shukla, deputy director general at the coal ministry, matters of pension revisions are dealt “on a case-to-case basis”.

The Wire also reached out to the CMPFO commissioner regarding the status of the revisions. Assistant Commissioner, CMPFO, Madhuresh Kumar Singh pointed to a Rs 47 crore-deficit in funds. “The matter is under review. Decisions are taken by the board of trustees. We do not know anything about it,” he said.

‘They claim insufficient funds, but the companies are making a profit’

P.T. Rao, who retired in 2001 as a senior finance executive from the SCCL in Telangana, receives a mere Rs 5,000 as monthly pension. “We have approached the central government many times, written to the prime minister, coal minister, etc. They keep saying they don’t have sufficient funds but the companies are making profits,” he alleged.

In July 2025, the parliament’s Public Accounts Committee (PAC), chaired by Congress general secretary and Lok Sabha member KC Venugopal, [tabled its report](#) in the House saying that the “failure of Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO) to take timely decision to redeem

debentures of Diwan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) resulted in [an] avoidable loss of Rs 315.35 crore”.

The PAC observed that money from the CMPFO was invested in the debentures of DHFL despite its “ill reputation”.

The committee had observed there has been “critical irregularity” on part of the Ministry of Coal to oversee the functioning of CMPFO which led to the failure to ensure safety of its investments due to “lackadaisical approach in redeeming debentures of DHFL despite adverse critical ratings.”

“The funds are not being diverted to the pensioners. We are the worst sufferers,” Rao said.

In 2015, petitioners, under the banner of Federation of Coal Industries Retired Employees Association, had approached the Delhi high court regarding the valuation and revision of the Coal Mines Pension Scheme.

According to the petitioners, the pension fund grew from Rs 21,033.27 crore in 2022-23 to Rs 22,898.90 crore in 2023-24, and stood at Rs 24,495.66 crore as of March 31, 2025.

Despite an apparent monetarily healthy position, they argued, the members of the pension fund are drawing a very meagre amount of pension due to non-revision at the end of the Board and the Union government.

The matter is expected to be listed before the Delhi high court on March 20.

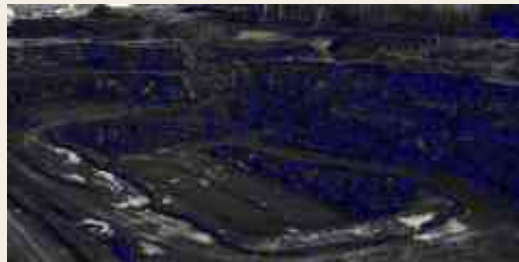
Meanwhile, coal pensioners have decided to stage a *dharna* at Jantar Mantar in New Delhi on March 30 to raise their demands.

The protest is being organised by AIACE-AICPA and other pensioners’ organisations. Ahead of the protest, Rathor said that the government should recognise the sacrifices of coal workers and take immediate action to resolve the long-pending pension issue, emphasising the need to draw national attention to the difficult conditions faced by thousands of elderly coal pensioners.

<https://thewire.in/rights/spent-our-lives-serving-the-nation-ex-coal-mine-employees-write-to-modi-over-pension-revision>

‘Spent Our Lives Serving the Nation’: Ex-Coal Mine Employees

Write to Modi Over Pension Revision



Sharmita Kar

24/Mar/2026

The pensioners have alleged that for decades, they have worked in some of the harshest and most hazardous conditions. Yet, they are now struggling to survive because the pension rates have fallen far behind the rising costs of living, medicines and basic necessities.

Representative image of a coal mine. Photo: Lachlan/Unsplash

New Delhi: Seventy-five retired coal mine employees, consisting of former chairmen, managing directors and directors of Coal India Limited and Singareni Collieries Company Limited, on Monday (March 23) wrote to prime minister Narendra Modi, urging him to address the issue of long pending pension revision, which they have repeatedly raised has remained unchanged without any revision since their retirement.

“We have superannuated from Coal India Ltd. (CIL) / its Subsidiary Companies and Singareni Collieries Company Ltd. (SCCL), after serving the nation for decades, many of us at the level of Chairman and Directors. Our collective efforts, along with lakhs of coal workers, have helped build these institutions into pillars of India’s energy security, contributing over 55% of the country’s commercial energy needs and generating more than Ra 70,000 crores annually for the national exchequer,” read a letter, dated March 23, 2026.

“The root of the problem is the fact that the pension fixed on the date of retirement, remains constant forever without any adjustment for rise in prices,” they said.

The retirement age for coal mine employees is 60 years. Many of the protesting pensioners are in the age bracket of 70-90 years now, facing serious health problems and struggling to meet daily expenses.

The Wire has previously [reported](#) that several top-level executives of these coal companies receive a pension of less than Rs 10,000 per month. The pension amount which, as per the Coal Mines Pension Scheme (CMPS), 1998, is to be reviewed every three years has not been revised for many employees since inception. Additionally, the 1998, 2007 and 2017 wage revisions for employees were also not applied to these pensioners.

The pensioners have alleged that for decades, they have worked in some of the harshest and most hazardous conditions, “comparable only to those of jawans in the armed forces, to power the nation’s growth and ensure energy security”. Yet, many of these retired workers are now struggling to survive because the pension rates have fallen far behind the rising costs of living, medicines and basic necessities.

“It is deeply concerning that pension in coal sector under CMPS-1998 has suffered due to corpus mismanagement and suboptimal investment decisions. These shortcomings have already been highlighted in the 12th Report of the Public Accounts Committee (Report No. 2193, presented on 18th March 2020). Though the Government had agreed to review and restructure the scheme, no meaningful corrective action has followed,” they have said.

The Coal Mines Provident Fund Organisation (CMPFO), the autonomous body which provides for the pension of coal sector employees, and falls under the Union coal ministry, has repeatedly told the pensioners that their pensions have not been revised due to a shortage of funds.

In October 2025, 77 years after the 1948 Act’s enactment, the Union government announced an overhaul by proposing a draft Bill, titled the [Coal Mines Employees’ Provident Fund and Miscellaneous Bill, 2025](#).

The Bill has not been tabled in the parliament yet.

In March last year, Modi, hailing the country’s achievement of 1 billion tonne coal production, called it a “historic milestone” and “proud moment for India”, and [recognised](#) the relentless dedication and hard work of those associated with the sector.

Highlighting this, the coal pensioners said that the “entire Coal Family of India felt proud” when this was declared. “Such proud moments are because of the dedication of today’s

workforce in coal (tomorrow's pensioners) and equally the contribution of the past workforce (today's pensioners)."

The pensioners have demanded the government to take immediate steps to substantially increase the coal pension so that retired miners and employees can "live their remaining years with dignity and security".

"It is an issue of justice, dignity, and national gratitude to those who spent their lives serving the nation from beneath the earth to keep the wheels of the economy running," they said.

They have also demanded the government to introduce a mechanism for periodic adjustment linked to inflation, ensure fair returns on contributions under CMPS-1998 and restore dignity and financial security for retired coal employees. Separately, they have also demanded that medical facilities be provided free of cost to retired employees and their spouses.

Notably, the All India Association of Coal Executives (AIACE) and the All India Coal Pensioners Association (AICPA) have been raising these demands for years.

"It is a matter of grave concern that while the coal sector – particularly Coal India Limited and Singareni Collieries Company Limited – has consistently contributed thousands of crores of rupees to the national exchequer in the form of taxes, royalties, and dividends, the very workforce that built and sustained this sector has been left neglected in their old age," the associations said in a letter on Monday to Securities and Exchange Board of India, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange of India.

The coal pensioners, led by AIACE and AICPA, have decided to stage a *dharna* at Jantar Mantar in New Delhi on March 30 to raise their demands.

New Telangana

Coal pensioners' strike

Solidarity of Singareni retired employees



New Telangana - Narapalli

In solidarity with the dharna held by the All India Coal Pensioners Association at Jantar Mantar in New Delhi on Monday demanding an increase in pension for coal sector employees, Singareni retired employees held a meeting in Korremula Suprabhat Township, Ghatkesar Circle, Greater Hyderabad. As part of this, they protested holding placards demanding that the pension scheme be revised every three years as per the Coal Mines Pension Scheme-1998 and that the pension be increased and that we want justice. Speaking on the occasion, Singareni Retired Employees Welfare Association General Secretary Alavandar Venu Madhav said, "Coal India Limited should pay a minimum pension of Rs. 10,000 to Singareni retired employees, and that the Coal Mines Pension Scheme should be revised to pay a pension with dearness allowance (DA) and provide financial security and free medical facilities." It is a complaint that the provision to revise pension every three years as per the Coal Mines Pension Scheme, which has been implemented since April 1998, is not being implemented.

He reminded that for the last five years, protests have been organized in cities like New Delhi, Varanasi, Kolkata, Kothagudem, Nagpur, and Godavarikhani to increase pension. He said that petitions have been submitted to the Prime Minister, Union Ministers, and members of Parliament. He expressed his concern that the pension is not sufficient to meet minimum basic needs due to the burden of old age, medical expenses in old age, and rising prices in the market. He demanded that the Coal Mines Provident Fund 2025 Draft Bill be introduced in Parliament, the Coal Mines Pension Fund be strengthened, a minimum pension of Rs. 10,000 be paid to coal sector employees, and a dignified life be provided in the society. In this meeting, Singareni Retired Employees Welfare Association Vice Presidents Bangari Rajaiah, K. Beeriah, Joint Secretary Samantula Narsing Rao, Geesa Kanakaiah, Kotte Malliah, M. Raja Nurse, CH. Narsayya, Rafiq, Madanayya, Rama Raju Subhash Reddy, Muninder Reddy, Rajamallu, T. Srinivas and a large number of retired employees of Singareni participated.

कोयला पेंशनरों का जंतर-मंतर पर धरना, प्रधानमंत्री को सौंपा मांग पत्र



नई दिल्ली (स्टेट मीडिया संवाददाता)। देशभर के कोयला पेंशनरों ने ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को जंतर-मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस दौरान पेंशनरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की ज्ञापन में पेंशनरों ने कहा कि वर्षों तक कठिन और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में देश की सेवा करने के बावजूद उन्हें पर्याप्त पेंशन लाभ नहीं मिल रहा है। वर्तमान पेंशन व्यवस्था महंगाई के अनुरूप नहीं है, जिससे बुजुर्ग पेंशनरों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है कोयला पेंशन में तत्काल संशोधन कर राहत प्रदान की जाए पेंशन में महंगाई राहत (DR) को शामिल किया जाए कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998 का समयबद्ध पुनर्गठन किया जाए हर तीन वर्ष में पेंशन का पुनरीक्षण सुनिश्चित किया जाए पेंशन कोष को मजबूत करने के लिए प्रभावी प्रबंधन और संसाधन बढ़ाए जाएं न्यूनतम पेंशन को सरकारी मानकों के अनुरूप तय किया जाए। पेंशनरों का कहना है कि खदानों में लंबे समय तक काम करने के कारण उन्हें कई गंभीर व्यावसायिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके चिकित्सा खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके, उनकी पेंशन स्थिर बनी हुई है और महंगाई के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही है ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 2020 की रिपोर्ट में भी पेंशन योजना की खामियों को उजागर किया गया था। लेकिन अब तक कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं।

Pravachanam Intranet Portal

Public purpose


31 Mar 2026 Editor: Samuni Reddy | Page 2
Source: epaper.prajalakshtyam.com

Pension revision guarantees should be implemented every three years

- Coal pensioners angry over no change for 30 years Protest
- in Bhupalpally in support of Jantar Mantar dharna

(Public representative)

Jayashankar Bhupalpally, March 30: Despite the promise to revise the pension scheme for coal miners every three years, Singareni pensioners have expressed their anger that it has not been implemented even after three decades. In this end, a dharna was held at Ambedkar Square in Bhupalpally district headquarters on Monday in support of the Maha Dharna held at Jantar Mantar in Delhi. Several pensioners participated in this program held under the auspices of Singareni Pensioners Association President Gundeti Sammayya. Speaking on the occasion, they criticized that as part of the pension scheme introduced for coal miners in 1998, it was proposed to revise it every three years; but it has not been revised even once so far. At present, the workers are getting a pension of between Rs. 300 and Rs. 1000, and it is very difficult to continue living with this small amount. He said that some pensioners are forced to beg for a living, and those who lived with dignity during their working years are now forced to work as cleaners on school buses and laborers in brick kilns. The backbone of the nation-building



He said that it is unfortunate that coal miners have to take to the streets for their survival today. He said that thousands of elderly people are living below the poverty line due to the lack of pension revisions for 30 years. He said that the legal battle on this issue has already reached the Supreme Court and the Delhi High Court, and in 2020, the PAC Commission also suggested the need for reforms, but it has not been implemented, he criticized. He said that a draft bill was proposed in 2025, but it has not been implemented. He recalled that recently 75 former CMDs wrote a letter to the Prime Minister and sought his intervention. They demanded immediate revision of pension, provision of dearness allowance in line with inflation, provision of government financial assistance to the pension fund, and transparent changes in management. "We have worked hard for the institution our entire lives... have we become useless after becoming a panditaka?" The pensioners expressed their grief. He said that the Mahadharna to be held at Jantar Mantar will be a decisive step to resolve the problems. Gatala Rajinidhi, Madugula Samesi Reddy, Betla Swamy, The Ashadapu Rangayya, Marupalli Ramaswamy, Gollu Mohan Reddy, Janga Lakshma Reddy, Thota Rajayya, Sheemayya, Saravaham and others participated in this program.

कोल पेंशनरों का दिल्ली में धरना प्रदर्शन, पेंशन रिवीजन की मांग



धनबाद. कोयला उद्योग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी कोल पेंशनरों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया. देश के विभिन्न कोलफील्ड क्षेत्रों से पहुंचे बड़ी संख्या में पेंशनरों ने पेंशन रिवीज, न्यूनतम पेंशन निर्धारण, महंगाई राहत और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की मांग को लेकर आवाज बुलंद की. इस

दौरान पेंशनरों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और केंद्र सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की अपील की. पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक पीके सिंह राठौर ने कहा कि वे लोग लंबे समय से अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार और संबंधित मंत्रालयों के समक्ष उठाते रहे हैं. लेकिन, अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है.